

उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित
विचारों का सुधारक होता है प्रेमचंद

फरोजशाह कोटला मैदान

भारत और श्रीलंका के बीच राजधानी के पिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली छह दोहरे शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए। लेकिन सुर्खियों में उनका पर्दशन होकर प्रदूषण रहा। श्रीलंकाई कोच निक पोथास ने खेल रुकने के बाद अंपायरों नाइजल लोंग और जोइल विल्सन के साथ मैच रेफी डेविड बून से यह कहा कि हमारे पास मैदान में उतारने के लिए फिर 11 खिलाड़ी ही नहीं हैं। मैच संचालकों के सामने यह अभूतपूर्व स्थिति थी और आईसीसी नियमों में भी ऐसी स्थिति से निपन्ने के लिए बहुत कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए वह समझ नहीं पा रहे थे कि खेल शुरू कराने के लिए क्या किया जाए। इस स्थिति में विगत कोहली ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए भारत की पारी घोषित कर दी। श्रीलंका के तीन खिलाड़ी चोटिल थे और दो तेज गेंदबाज वांस लेने के दिक्षित होने की वजह से ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे। श्रीलंका के कोच निक पोथास ने अपने क्रिकेटरों के मैदान से बाहर आकर इस प्रदूषण की वजह से उल्लिख्यां करने की बात कहने से बात गंभीर दिखती है। लेकिन जवाब में बीसीसीआई अधिकारियों का यह कहना कि जब दर्शक दीर्घा बैठे 20000 दर्शकों को कोई दिक्षित नहीं हो रही है तो श्रीलंका इसे मुद्दा क्यों बना रही है। यह भी कहा गया कि जब विराट कोहली बिना किसी दिक्षित के दो दिन बल्लेबाजी कर सकते हैं तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों को क्यों दिक्षित हो रही है? यह सब कहने की कोई तुक नजर नहीं आती है। इस घटना के समय कोटला मैदान पर हवा की क्लाइटी का इंडेक्स 240 था और प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड के मुताबिक इस स्थिति में गहन शारीरिक गतिविधियां करना नुकसानदायक है। राजधानी में स्मॉग की स्थिति जाड़ों में अक्सर ही खराब रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही स्थिति इतनी खराब थी कि छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए थे और कहा गया था कि इन दिनों सुबह टहलने से बचें। वैसे भी एक तेज गेंदबाज को गेंदबाजी करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ऐसे में श्रीलंका के तेज गेंदबाजों को वांस लेने में दिक्षित महसूस करना संभव है। यह मैच तो किसी तरह चलता रहा। लेकिन इससे राजधानी की आबोहवा को लेकर ऐसा लगाने लगा है कि हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब यहां अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन करने में आयोजक करताने लगेंगे।

औपचारिकता

राहुल गांधी ने एक और कांग्रेस अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भरा। दूसरी ओर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी तीखी आलोचना की। वस्तुतः प्रधानमंत्री का पूरा पोक्स कांग्रेस में वंशवादी नेतृत्व पर था। वे यह बताना चाह रहे थे कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा वहां ऐसा ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री यदि राहुल गांधी या नेहरू-इंदिरा वंश की तुलना शाहजहां और औरंगजेब से नहीं करते तो अच्छा होता। किंतु कांग्रेस इस सच्चाई को नकार नहीं सकती कि अगर राहुल गांधी उस वंश के वारिस नहीं होते तो उन्हें अध्यक्ष पद के लिए इतना व्यापक समर्थन पार्टी में नहीं मिलता। जहां तक आंतरिक लोकतंत्र का प्रश्न है तो भारत में आज शायद ही ऐसी कोई पार्टी है जिसमें पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। भाजपा भी इसका अपवाह नहीं है। हर पार्टी में चुनाव होता है, लेकिन यह केवल औपचारिकता मात्र है। किसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यों से नामित होकर नहीं आते हैं। पहले अध्यक्ष का नाम तय हो जाता है और सर्विधान के अनुरूप उसका केवल अनुमोदन कराया जाता है राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव भी ज्यादातर राज्यों से आ गया है। इस नामे कांग्रेस भी कह सकती है कि राहुल चुनाव प्रक्रिया से यह तक पहुंचे हैं। किंतु सच यही है कि उनका नाम पहले से तय था राज्यों को केवल उनका नाम भेज देना था। किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई और नाम भेज सके। भाजपा के अमित शाह आज अध्यक्ष हैं, उनका भी बाकायदा निर्वाचन हुआ है। लेकिन वह निर्वाचन भी ऐसा ही था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके अध्यक्ष बनने का निर्णय पहले किया और सारी सर्वैधानिक प्रक्रियाएं बात में पूरी हुईं। इसलिए देश की हर पार्टी को इस मामले पर आत्मरचित्तन की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि लगभग सारी पार्टीयां आंतरिक लोकतंत्र से विरत हो चुकी हैं? चूंकि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं हैं, निर्धारित तरीके से चुनाव नहीं होते, इसलिए नेताओं में भी लोकतांत्रिक संस्कार घनीभूत नहीं होते। इसका शिकार हमारा लोकतंत्र भी हो रहा है। राहुल के अध्यक्ष पद पर चयन के साथ यदि आंतरिक लोकतंत्र पर ईमानदार बहस हो तो यह देश के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा।

सहस्रंग

କୌଣସି

न मारा जा सकता है न जीता जा सकता है, केवल समझा जा सकता है और केवल समझ ही रूपांतरण लाती है, बाकी कुछ नहीं। तुम अपने भय को जीतने की कोशिश करोगे तो यह दबा रहेगा। भय को तुम दबा सकते हो। वह तब भी तुम पर हावी होगा, तुम पर कब्जा करेगा लेकिन ऐसे परोक्ष ढंग से कब्जा करेगा कि तुम्हें उसका पता भी न चले। लेकिन तब खतरा और भी गहरा हो जाएगा। तो भय को जीतना नहीं है। भय को तुम मार नहीं सकते क्योंकि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है और कोई भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। क्रोध और भय, दोनों एक ही ऊर्जा के दो आयाम हैं। क्रोध आक्रामक है और भय अनाक्रामक। तुम क्रोध में होते हो तो तुममें कितनी ताकत आ जाती है, ऊर्जा भर जाती है। क्रोध में होते हो तो एक बड़ी चट्ठान भी उठाकर फेंक सकते हो; आम तौर पर उतनी बड़ी चट्ठान तो तुम हिला भी नहीं सकते। तुम किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसका रूप बदल सकते हो। युगां-युगां से यही किया गया है-लोग भय को नष्ट करने की, क्रोध को, काम को, लोध को और ऐसी कितनी ही चीजों को नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? मनुष्य उथल-पुथल हो गया है। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वसा है, बस चीजें उलझ गई हैं। कुछ भी नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात कुछ भी नष्ट किया ही नहीं जा सकता। तो पिर क्या करना है? भय को तुम्हें समझना है। भय क्या है? कैसे उठता है? कहां से आता है? उसका संदेश क्या है? बिना किसी पक्षपात के उसमें ज़ांको, तभी समझ पाओगे? तुम्हारी पहले से ही धारणा बनी हुई है कि भय गलत है, कि भय नहीं होना चाहिए-“मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए”-तब तुम उसमें ज़ांक न पाओगे। भय का आमना-सामना तुम कैसे कर सकते हो? तुमने पहले से ही निर्णय ले लिया है कि भय तुम्हारा दुश्मन है, तो उसकी आंखों में तुम कैसे ज़ांक सकते हो? तुम सोचते हो कि यह गलत चीज है तो तुम उससे बचकर निकलना चाहोगे, उसकी उपेक्षा करना चाहोगे। पहले सारे पूर्वग्रह, सारी धारणाएं, पूरी निंदा को छोड़ो। भय एक तय है। उसका सामना करना है, उसका समझना है। और केवल समझ के द्वारा ही उसे रूपांतरित किया जा सकता है। वास्तव में समझने से ही वह रूपांतरित हो जाता है। बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है; समझ ही उसे रूपांतरित कर देती है।

ਪੇਂਸ਼ਨ ਭੋਗਿਆਂ ਕੋ ਪਿਤ੍ਰੂ ਤਰ੍ਹਾਂ

केंद्र सरकार से सेवक आफिशर पद से रिटायर होने वाले कर्मी को मासिक 40 हजार रुपये से अधिक तक की मासिक पेंशन मिल जाती है। पीएफ ग्रैच्यूटी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज जैसे और दूसरे लाभ तो मिलते ही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से रिटायर कर्मियों का आंकड़ा बमुश्किल तीन-चार करोड़ होगा। इसमें केंद्र और राज्यों उपक्रमों में काम कर रहे या सेवानिवृत्त कर्मियों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा पांच-छह करोड़ के आसपास हो जाता है। लेकिन इनमें सबको पेंशन नहीं मिलती।

आकड़ा पाच-छह कराड़ के आसपास हा जाता ह। लाकन, इनम सबका पशन नहा मिलता

सतीश पेडणोक

30 नवम्बर तक निजो क्षेत्र का कपानियो से सवानीनवृत हो गए, कर्मी अपने ही बैंकों के चक्कर काट रहे थे। इन बैंकों में उनकी सांकेतिक पेंशन आती है। दरअसल, इन्हें बैंकों में इसलिए जाना पड़ रहा था ताकि वहां पर जाकर बता सकें कि अभी भी जीवित हैं इस संसार में। यह एक वार्षिक कार्य है, जो इन पेंशनभोगियों को पितृ तर्पण की तरह हर साल करना ही पड़ता है। इन सभी को मिलती है मासिक 1250 से लेकर 10 हजार रुपये तक की पेंशन। समझ सकते हैं कि इतनी कम राशि में अपने और अपनी बूढ़ी औरत के किराये की तो बात न ही करें तो अच्छा होगा। हाँ, केंद्र और राज्य सरकारों के रिटायर कर्मियों को तो पेंशन अब संतोषजनक सी मिलने लगी है। केंद्र सरकार से सेक्षण आफिसर पद से रिटायर होने वाले कर्मी को मासिक 40 हजार रुपये से अधिक तक की मासिक पेंशन मिल जाती है। पीएफ ग्रैच्यूटी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज जैसे और दूसरे लाभ तो मिलते ही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से रिटायर कर्मियों का आंकड़ा बमुश्किल तीन-चार करोड़ होगा। इसमें केंद्र और राज्यों उपक्रमों में काम कर रहे या सेवानीनवृत कर्मियों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा पांच-छह करोड़ के आसपास हो जाता है। लेकिन, इनमें सबको पेंशन नहीं मिलती। इनको तो एक तरह से कुछ न कुछ सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। पर बाकी की स्थिति तो दिन-ब-दिन बद से बदतर ही होती जा रही है। निजी क्षेत्रों में तो छोड़ ही दें, ज्यादातर सरकारी विभागों और उपक्रमों में भी अब ठेके पर ही कर्मियों को रखा जा रहा है। ज्यादातर को उनकी रिटायरमेंट से पहले ही चलता कर दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक होने पर वे तिल-तिल को मोहताज हो जाते हैं। सबसे विकट स्थिति है देश में असंगठित क्षेत्रों से जुड़े करोड़ों कामगारों की। इनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या कोई सोच रहा है? इनकी छत, भोजन, बीमार होने पर दवाई वगैरह की व्यवस्था किस तरह से होती है? स्वास्थ देखभाल और बुद्धापा पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ही मिलते हैं। गैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की बात करें तो इन्हें सही तरह से सरकारी योजनाओं के लाभ तक नहीं मिल पाते। देश की कुल श्रम शक्ति का 90 पीसद हिस्सा असंगठित क्षेत्रों से ही जुड़ा है। साठ साल की उम्र के बाद इनका क्या होता होगा? एक बढ़िया सरकारी योजना मोदी सरकार लाई है, “अटल पेंशन योजना”。 लेकिन इसका लाभ सिर्फ कामगार ही ले सकता है, वह भी सिर्फ अपने लिए। उसके पास न तो अतिरिक्त पैसा होता है न ही इतने साधन या समय कि योजना का लाभ लेने के लिए चक्कर काटे या सालाना नवीनीकरण करवाए। कुछ बड़े संस्थानों ने पैसे देकर अपने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ

नहीं मिलना चाहिए, इसके तक को तो पेंशन मिलनी ही है, दूसरों को क्यों न मिले, इसके लिए अपनी बाबूगिरी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा कि हमारे यहां युवा शक्ति की चर्चा बहुत होती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परंतु इस क्रम में उनकी अनदेखी न हो जिन्होंने जीवन भर देश के लिए दिन-रात एक किया। बुजुगरे की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके अनुकूल स्थितियां बनानी होंगी। बुजुगरे को अलग-थलग या उपेक्षित तो नहीं छोड़ा जा सकता। पिछ्ले एक दशक में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में 39.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, और देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी वर्ष 2001 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2011 में 8.3 प्रतिशत हो गई है। बेशक, सरकार के अनेक सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इनके लाभार्थी सीमित ही हैं। इनमें असंगठित क्षेत्रों के बहुत कम कामगार या उनके परिवार लाभार्थियों में शामिल हो पाते हैं। गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को बीमारी, अधिक उम्र, दुर्घटनाओं या मृत्यु के कारण बेहद गरीबी का सामान करना पड़ता है। आप



संवदनहान रुख अपनाए हुए हैं। इनका सुख-सुविधा के लिए अनेक तरह के कदम भी हाल के वर्षों में उठाए गए हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और समाज हरेक बुजुर्ग के प्रति संवेदनशील रखें या अपनाए। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में देश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले बुजुरगे को कम से कम छत, दवाई, भोजन की व्यवस्था तो अवश्य ही हो।

चलते चलते

फोर्ब्स की लिस्ट

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई। जो बदे या बंदी चालू हैं, उनकी विकास दर इससे भी बहुत ज्यादा रही होगी। इधर, तरह-तरह की आर्थिक खबरें आती हैं। कई बार लगता है कि इनसे हमारा रिश्ता क्या है। फोर्ब्स की लिस्ट में इन्हने अरबपति भारत के। मतलब क्या इन खबरों से नॉन-अरबपतियों को प्रेरित होना चाहिए और लग जाना चाहिए अरबपति बनने। लखपति बनने की कोशिश भी कामयाब होती है।

न हान दत तमाम कपना वाल । एक बार
बीस हजार रुपये पढ़े थे मेरे पास, इन्हें
इश्तिहार आए कि बीस हजार देकर बाकी
की नब्बे हजार की रकम ईमआई में दे
दो और वो वाला मोबाइल ले लो । घरवालों
ने मार मचा दी कि ले वो वाला मोबाइल,
बीस हजार मेरे निकल गए । उस उद्योगपति
के पास पहुंच गए, जिसका नाम

अरबपतियों की लिस्ट में था । अरबपति कोई कैसे
बन जाता है, क्योंकि वह बीस हजार उसकी जेब से
निकाल लेता है, जो खुद लखपति बनने की आकांक्षा
पाले हुए था । कोई अरबपति बने, इसके लिए जरूरी
है कि कोई किसी की जेब में बीस हजार न रहें मेरी
न बढ़ी इनकम, 6.3 प्रतिशत जीडीपी कैसे बढ़ गई
देश की । क्या मैं देश में नहीं हूं । मैं समझता हूं खुद

को बेटे बढ़ातरी वाला देश तेरा न है। बढ़ोतरी वाला देश कोई और है, कहीं और रहता है। मैं बढ़ातरी तो दूर, पुरानी इनकम बनी रहे, इस पर ही परेशान रहता हूँ। नव्यु पकौड़ीवाला इस परेशानी में न रहता, यद्यपि वह ग्रेटर कैलाश में भी नहीं रहता। उसने पकौड़ी के रेट दस प्रतिशत बढ़ा दिए। पब्लिक पकौड़ी के रेट बढ़ा कर दे दे देती है, लेखक किताबों के पांच परसेंट रेट बढ़ाकर मांग ले, तो पाठक लेने से इनकार देता है। हिंदी के लेखक की जीड़ीपी उसके शालों से नापी जाए, जो हर साल करीब दस परसेंट बढ़ जाती है। बाकी दुनिया भर के पेशों की जीड़ीपी रकम की शक्ति में बढ़ती है, हिंदी के लेखक की जीड़ीपी शाल में बढ़ती है। किसी को कुछ रकम मिल जाए, तो वह उसे बाजारू घोषित कर देते हैं, जिन्हें अपनी किताब भी रकम देकर छपवानी पड़ती है। हिंदी का लेखक कुछ रकम भी इस तरह से अंदर करता है, जबरदस्त छलांग लगाई। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूँडीज ने भारत का दर्जा बढ़ाया। पर्स एक दूसरी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हालांकि दर्जा तो नहीं बढ़ाया, लेकिन यह माना कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है। जब आधार सशक्त हो, तो अर्थव्यवस्था का विकसित होना स्वाभाविक परिणाम होता है। इस बीच आर्थिक विकास दर में उतार-चढ़ाव सामान्य बात होती है। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद (जीड़ीपी) की वृद्धि दर में कभी गिरावट आए, तो यह मातम का विषय नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सियासी होड़ में जुटे विरोधी दल या नेता ऐसे मामलों पर भी दीर्घकालिक नजरिया नहीं अपनाते। इसके बजाय वे ऐसे राजनीतिक कथानक बनाने में जुटे रहते हैं, जिससे सरकार को नाकाम बताया जा सके।

ऐसा ही तीन महीने पहले हुआ, जब केंद्रीय सारिव्यकी संगठन (सीएसओ) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े जारी किए। तब जीड़ीपी की विकास दर गिरकर 5.7 फीसदी पर आ गई। विपक्ष ने इसे नोटबंदी का नतीजा बताया। इस आधार

उत्साहजनक संकेत

कुछ समय पहले विश्व बैंक की ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस (कारोबार में आसानी) सूची में भारत ने 30 पायदान की जबरदस्त छलांग लगाई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का दर्जा बढ़ाया। फिर एक दूसरी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुर्स ने हालांकि दर्जा तो नहीं बढ़ाया, लेकिन यह माना कि भारत की अर्थिक बुनियाद मजबूत है। जब आधार सशक्त हो, तो अर्थव्यवस्था का विकास होना स्वाभाविक परिणाम होता है। इस बीच अर्थिक विकास दर में उत्तर-चढ़ाव सामान्य बात होती है। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में कभी पिरावट आए, तो यह मात्र का विषय नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सियासी होड़ में जुटे विरोधी दल या नेता ऐसे मामलों पर भी दीर्घकालिक नजरिया नहीं अपनाते। इसके बजाय वे ऐसे राजनीतिक कथानक बनाने में जुटे रहते हैं, जिससे सरकार को नाकाम बताया जा सके।

ऐसा ही तीन महीने पहले हुआ, जब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े जारी किए। तब जीडीपी की विकास दर गिरकर 5.7 प्रैसदी पर आ गई। विपक्ष ने इसे नोटबंदी का नतीजा बताया। इस आधार पर केंद्र को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन वो

मुद्दा

पंचायतों और स्थानीय चुनाव

वर्तमान में यह एक मजबूत तर्क स्थापित हुआ है कि पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की प्रतीत शैक्षणिक योग्यता से निर्धारित हो सकती है, तो संसद और विधान सभाओं के लिए क्यों नहीं? गुजरात निकाय चुनाव, राजस्थान और हरियाणा पंचायत चुनाव में प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने के पश्चात अब संसद और विधान सभाओं में चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता तय करने की मांग बलवती होने लगी, क्योंकि इन प्रावधानों का लाभ उन सभी राज्यों के पंचायत और निकाय चुनावों में देखने को मिला है, जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। बीते कुछ वर्षों से सांसदों और विधायिकों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने की मांग विभिन्न मंचों से लगातार उठती रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि देश में विधायक और सांसद पढ़े-लिखे लोग बर्नेंगे तो देश का अभूतपूर्व विकास संभव होगा। लेकिन देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और अधिकांश ग्रामीण निरक्षर हैं। इसलिए पहले यह जरूरी है कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरु स्त और गुणवत्तापूर्ण कर लें। कई सांसद ऐसे भी हैं, जो संसद की कार्यवाई में बिल्कुल शांत और निरीव बने रहते हैं। संसद को बौद्धिक और आदर्श स्थिति में लाने के लिए कई संस्थान और संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। फलस्वरूप निजी विधेयक पेश करने की संख्या बढ़ी है, और संसदीय प्रश्नों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। इन सबके बावजूद बहुत सारे हितबद्ध समूहों द्वारा शैक्षणिक योग्यता के प्रवधानों के खिलाफ इस तरह की दलीलें भी दी जाती हैं कि ऐसा जरूरी होता तो संविधान निर्माण के समय ही ऐसा प्रावधान किया जाता। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय के भारत की तुलना आज के वैश्वीकृत भारत से करें तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत विश्व मानिचत्र पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्शाता है, ऐसे में हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरंतर परिष्कृत करते रहना होगा। लंबे समय से लोकतांत्रिक सुधारों के प्रति जनता बहतर प्रावधानों की मांग करती रही है। इनमें राजनीति में अपराधियों को रोकने से लेकर जनप्रतिनिधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और उनसे नाखुश होने की स्थिति में उन्हें वापस बुलाने का अधिकार तक शामिल हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद लोकतंत्र की इस पवित्र व्यवस्था में अपराधियों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक पाने में हम सफल नहीं हो सके हैं। ऐसोसिएशन फॉर डेमक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मुताबिक 16 वीं लोक सभा में चुने गए कुल प्रत्याशियों में से 34 प्रतिशत यानि कुल 185 सांसदों पर आपराधिक

मामले लंबित हैं। हालांकि राजनीति में दागियों के प्रवेश और प्रभाव को रोकने के प्रति सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग काफी गंभीर रहे हैं। विस्तृत रूप से लोकतांत्रिक सुधारों की बात करें तो काफी कृष्ण करने की जरूरत है। राजनीति में अपराधियों को आने से रोकने का आर्थिक प्रयास एडीआर ने किया। उसने जनिहत याचिका दायर की जिस पर 2 नवम्बर, 2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि लोक सभा या राज्य विधानसभा के प्रत्याशी सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करें कि उन पर कोई आपराधिक मामला है कि नहीं। न्यायालय के इन फैसलों से भारत में वास्तविक और जिम्मेदार लोकतंत्र की वापसी का संकेत मिला है। किंतु यह काफी नहीं है, वर्तमान की राजनीतिक दशा और दिशा को ध्यान में रखते हुए हमें और भी व्यापक प्रयास करने की जरूरत है। जनता को भले ही नकारात्मक मत देने का अधिकार दे दिया जाए किन्तु जब तक जनता अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, यह अधिकार किसी काम का नहीं है। वर्तमान में लोकतंत्र के मार्ग की बाधाओं और मतदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में सांसदों के लिए तथ शैक्षणिक योग्यता का मानक स्थापित हो तो इन समस्याओं का भी समाधान संभव है।

जारी किए, तो सामने आया कि आर्थिक विकास दर 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जिन क्षेत्रों में 6 फीसदी से ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई, उनमें मैन्युफैक्चरिंग (कारखाना), बिजली, गैस, जल आपूर्ति, होटल, परिवहन एवं संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।

इनका विश्लेषण करें तो जाहिर होगा कि उत्पादन और उपभोग, दोनों ही मामलों में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। अनेक अर्थशास्त्री मानते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फार्मेंशन (अचल पूँजी में हुए धन का निवेश) अर्थव्यवस्था की सेहत का जीडीपी विकास दर से कहीं अधिक वास्तविक सूचकांक है। इस कसौटी पर भी देखें, तो इसके चालू एवं नियत मूल्यों पर क्रमशः 6.3 और 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2016-17 की दूसरी तिमाही में यह 2.9 और 3.0 फीसदी रहा था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर मिछले तीन महीने से जारी चर्चाओं की दिशा अब बदल जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होना सत्ताधारी भाजपा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कांग्रेस ने वहां नोटबंदी और जीएसटी के कारण पेश आई कथित दिक्टितों और आर्थिक गिरावट को केंद्र में रखकर अपने चुनाव अभियान का कथानक बुना। अब इसका आधार ही खिसक गया है। बहरहाल, राजनीतिक लाभ-हानि के बजाय देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस अच्छी खबर पर बात होनी चाहिए। ये दरअसल हम सबकी खुशहाली की खबर है। वैसे सरकार के लिए अभी चैन से बैठने का वक्त नहीं आया है। आठ प्रतिशत से ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने का उसका घोषित लक्ष्य अभी भी दूर है।

